आप लेट हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो बेअंत सिंह, चीफ मिनिस्टर ने उस वक्त कहा था कि मैं अपने खर्चे से शुरू करुंगा बशर्ते की आपका कोलोबोरेशन हो। उन्होंने कोलोबोरेशन लिया और लेकर वहां पर इंस्टीटयूट नवम्बर, 1995 में शुरू किया। जो क्वेश्चन है चेयरमैन सर यह निफ्ट का है। यह कहा जाता है कि नार्दन इंडिया का जो पंजाब में लगाया गया है इसकी दो आइज हैं। तो साइमलटेनियसली उसका एक ही है जिस तरह से कहा जा रहा है वह बात गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है।

दूसरी बात यह है कि मेम्बर ने कहा कि इसके ऊपर बहुत सारे इल्जामात हैं, इरेग्युलरिटीज है। कमेटी डालने की जरूरत है। अभी अभी नवम्बर में शुरू हुआ है और उसमें जो कोलोबोरेशन निफ्ट के साथ है जो यहां दिल्ली में है वह उसको टेक्नालाजी का पूरा कोआपरेशन दे रहे हैं। उनकी जो जो जरूरियात हैं उसमें भी उनकी सहायता कर रहे हैं ताकि वह इंस्टीटयूट ऊपर आए।

DR. D. MASTHAN: Is there any institute in any other State, which has been set up in collaboration with NIFT?

SHRI G. VENKAT SWAMY: No.

DR. D. MASTHAN: Then, will the Minister take necessary steps to set up such institutions in other States?

SHRI G. VENKAT SWAMY: We will consider about it in future.

MR. CHAIRMAN: Mr. Surinder Singh Singla.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Sir, I am Surinder Kumar Singla.

MR. CHAIRMAN: I am sorry.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Mr. Chairman, Sir, I am extremely grateful to the hon. Minister for agreeing to help the State of Punjab in this direction. In fact, being a Member of the Textile Commission, I am myself persuading him to do this, but the problem is still pending. It is true that today Punjab produces around 25 per cent of cotton in the country. There is a potential for export of garments from Punjab. What is really needed and for which I have been persuading him is to open up a textile garments park. It is actually connected with this. The Centre need not spend a single paisa for putting up this project. May I know from the Hon. Minister whether he would consider the proposal for setting up of a garment industrial park in Punjab so that we could adequately and properly contribute our share in terms of increasing export of garments to other countries in the world?

श्री जी० वेंकट स्वामी: सर, अगर पंजाब गवर्नमेंट ऐसी कोई प्रोपोज़ल देती है तो गवर्नमेंट आफ इंडिया मिनिस्ट्री आफ टैक्सटाइल चाहती है कि हर सिटी के अंदर टैक्सटाइल सिटी हो, हर कैपिटल के अंदर टैक्सटाइल पार्क हो और मैं माननीय सदस्य को एशोरेंस देता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई ऐसी प्रोपोज़ल आए तो उसको हम एक्सैप्ट करेंगे और जितनी मदद चाहिए उतनी करेंगे।

Location of TV Transmitter at Basot

*162. SHRI JALALUDIN ANSARI:† SHRI RAJ NATH SINGH:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the location of the land identified for setting up a TV transmitter at Basot in District Almora, U.P.;

(b) whether the land has been handed over to Doordarshan;

(c) if so, by when the work on the project is likely to start; and

(d) if not, the reasons therefor and who is responsible for the delay which is affecting the commissioning of the TV transmitter scheduled to start functioning by July, 1996?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI P.M. SAYEED): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Suitable site/buildings for setting up of TV projects are required to be provided, to Doordarshan by the respective State Governments. No readymade building at Basot was made available by the State

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Jalaludin Ansari.

Government for setting up of the VLPT resulting in some delay in implementation of the project. A suitable site for setting up of the Very Low Power TV transmitter (VLPT) at Basot has since been identified and financial sanction for purchasing the same issued. Construction work would commence as soon as possession of the identified site is handed over to Doordarshan. Transmitter equipment for the project has already been procured. The VLPT is expected to be completed during 1996.

श्री जलालुदीन अंसारी: सभापति महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि बासोट (उत्तर प्रदेश) में स्थापित किए जाने वाले टी०वी० ट्रांसमीटर हेतु सरकार द्वारा स्थल की शिनाख्त कर ली गई है, तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह शिनाख्त कब की गई? टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने के लिए अनुमानित राशि क्या है एवं सरकार द्वारा स्थल पर कब तक कब्जा मिलने की संभावना है?

†श्री जलालुद्दीन अंसारी: सभापति महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि बासोट (उत्तर प्रदेश) में स्थापित किए जाने वाले टी०वी० ट्रांसमीटर हेतु सरकार द्वारा स्थल की शिनाख्त कर ली गई है, तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह शिनाख्त कब की गई? टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने के लिए अनुमानित राशि क्या है एवं सरकार द्वारा स्थल पर कब तक कब्जा मिलने की संभावना है?

SHRI P.M. SAYEED: Mr. Chairman, Sir, the hon. Member wanted to know about commissioning of a Very Low Power TV transmitter (VLPT) at basot in the district of Almora, U.P. Initially our policy is that for such T.V. projects, land should be made available by the State Governments free of cost. That is the policy of the Government. But, Sir, in this case they have identified two "nali" land which was not suitable for the project to be set up. This was made known to the district authorities and they tried to locate some building. Normally we take a VLPT/LPT on rent. The land was not made available and the building also was not made available to us. They have ear-marked hardly one-third acre of land which means two "nalis". But that is less than the land required for LPT. I would like to share with the House information with regard to allotment of land for various transmitters with the House. For the purpose of a high-powered transmitter seven acres of land is to be made available and for a very low-powered transmitter 105 square matres inbuilt area– carpet area and 1,500 square metres of open area is necessary. This land falls short of that. But as a special case in spite of land not being made available and a building not being made available we have accepted their proposal and we have issued a sanction letter. As soon as land is made available, possession of a building is made available we sould try to see that it is done.

श्री जलालुदीन अंसारी: महोदय, जैसाकि मंत्री जी ने कहा है कि वर्ष 1996 के अंत तक यह ट्रांसमीटर चालू किए जाने की संभावना है, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि यह कैसे संभव होगा जब कि सरकार को अभी स्थल ही नहीं सौंपा गया है तो उपकरण लगाने का काम किस रूप में शुरू किया जा सकता है और यह कार्य वर्ष 1996 में कैसे संपन्न हो सकेगा?

†श्री जलालुद्दीन अंसारी: महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि वर्ष 1996 के अंत तक यह ट्रांसमीटर चालू किए जाने की संभावना है, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि यह कैसे संभव होगा जब कि सरकार को अभी स्थल ही नहीं सौंपा गया है तो उपकरण लगाने का काम किस रूप में शुरू किया जा सकता है और यह कार्य वर्ष 1996 में कैसे संपन्न हो सकेगा?

†Transliteration in Arabic Script

(सक्षम ही नहीं सौंपा गया है तो ट्रांसमीटर लगाने का काम किस रूप में शुरू किया जा सकता है- और ये कार्य कब तक 1996 में कैसे संपन्न हो सकेंगे।)†

श्री पी०एस० सईद: आदरणीय माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होगी कि धनराशि सरकार सेंक्शन कर चुकी है। अब वही जगह जो हम को बताई गयी है, आयडेंटीफाय की गयी है, वही जगह हम ने भी एक्सेप्ट की है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट की है। अब सिर्फ हमें उस का पजेशन देने की बात है और हमारी उम्मीद है कि 1996 तक, जब तक कि वह लेंड पजेशन दे देंगे, एकाध महीने के अंदर स्टेट गवर्नमेंट हम को लेंड पजेशन दे देगी, तब हम 1996 को अंतर्गत ही यह स्कीम लागू कर देंगे।

श्री राजनाथ सिंह: मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि जब कभी भी किसी टी०वी० ट्रांसमीटर परियोजना को स्थापित करना होता है तो शासन की तरफ से उस क्षेत्र का सर्वे भी कराया जाता है कि इस टी०वी० ट्रांसमीटर परियोजना के स्थापित करने के बाद कितने गांव और कितने लोग लाभांवित होंगे? महोदय, निश्चित रूप से इस प्रकार का परीक्षण शासन द्वारा कराया गया होगा, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कितने गांव और कितने लोग इस टी०वी० ट्रांसमीटर परियोजना की स्थापना के बाद लाभांवित होंगे? साथ ही मैं यह भी जानकारी चाहूंगा कि इस परियोजना को स्थापित करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा कब लिया गया था और माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा कि धनराशि की मंजूरी दे दी गयी है, तो वह धनराशि की मंजूरी कब दी गयी और कितनी राशि की मंजूरी दी गयी है, इस का भी उत्तर मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा?

श्री पी०एम० सईद: आदरणीय सभापति जी, विद्वान सदस्य ने अपने सवाल में दो पहलू उठाए हैं। अगर मैं उनके सवाल को ठीक से समझ सका हूं तो एक तो उन्होंने यह पूछा है कि सर्वे करते हैं या नहीं और यह स्कीम लागू करने से कितने लोगों को इस का लाभ पहुंचेगा? सभापति जी, एक एल०पी०टी० के अंतर्गत लगभग 15 किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं, वह कभी-कभी 15 से 20 भी हो सकता है, उतने लोग एल०पी०टी० से लाभांवित हो सकते हैं, ऐसा हमारा सर्वे है। दूसरा पहलू उन्होंने धनराशि का उठाया है। अब यह जो जगह है, "एज ए स्पेशल केस" हम ने उस दोनाली जगह को पचेंज करने के लिए ही तय किया है और उस जगह को पचेंज करने के लिए 10 हजार रुपए की धनराशि का उन्होंने इवैलुएशन रखा है। वह रिलीज की गयी है, मगर उस के साथ-साथ यह ट्रांसमीटर की कॉस्ट और कोटा केबिन की कास्ट उस के अलहदा है। कोटा केबिन का 25 हजार का एसेसमेंट किया गया है और ट्रांसमीटर का वह सब मिलाकर इस में 1 लाख से भी ज्यादा धन राशि की जरूरत पड़ती है।

†Transliteration in Arabic Script

सभापति: श्री अनंतराय देवशंकर दवे।

श्री राजनाथ सिंह: मान्यवर, एक सप्लीमेंटरी और।

MR. CHAIRMAN: No more supplementary. Do you want to put another question? (*Interruptions*)

श्री राजनाथ सिंह: जी हां।

MR. CHAIRMAN: No, no. If you want to ask for any clarification, you can do so.

श्री राजनाथ सिंह: जी, क्लैरिफिकेशन। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में जो लो पावर ट्रांसमीटर्स स्थापित किए गए हैं, उनमें से क्या अधिकांश पावर ट्रांसमीटर्स इस समय काम नहीं कर रहे हैं और साथ ही यह भी जानना चाहूंगा कि पर्वतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, पर्वतीय संस्कृति को समृद्ध करने के लिए शासन के द्वारा जो प्रोग्राम प्रोडक्शन सेंटर स्थापित किए गए हैं क्या यह प्रोग्राम प्रोडक्शन सेंटर काम कर रहे हैं? यदि काम कर रहे हैं तो शासन द्वारा इन्हें क्या दिशा-निर्देश दिए गए हैं? और, यदि नहीं काम कर रहे हैं तो क्या यह प्रोग्राम प्रोडक्शन सेंटर समुचित रूप से काम करने लगें इस संबंध में शासन कुछ विचार कर रहा है?

श्री पी० एम० सईद: सभापति जी, यह जो सवाल है यह मुख्य सवाल से नहीं उठता है। यह सवाल सिर्फ बासोट वी०एल०पी०टी० की स्थापना से संबंधित है, मगर मैं इनके क्लैरिफिकेशन का जवाब दे सकता हूं। ...(**व्यवधान**).... दो मिनट में मेरे पास जो इंफोरमेशन है, मैं इनसे शेयर करना चाहूंगा। वह यह कि जो वह एच०पी०टी० था या आपने प्रोग्राम प्रोडक्शन सेंटर के बारे में पूछा कि वह कहां कहां अभी काम करते हैं, आपको वह मालूम होगा, मैं यहां पर बता सकता हूं कि हाई पावर ट्रांसमीटर ....(**व्यवधान**)....

श्री राजनाथ सिंह: महोदय, मैंने यह जानना चाहा है कि लो पावर ट्रांसमीटर पर्वतीय क्षेत्र में इस समय काम नहीं कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Mr. Raj Nath Singh, please sit down.

श्री पी० एम० सईद: सर, यह कौन से पर्वतीय क्षेत्र में काम नहीं कर रहे, अगर माननीय सदस्य कुछ जानकारी देते हैं तो जरूर हम उसके ऊपर पूछताछ करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसे ही एक जनरल कहने से नहीं होगा। सर, ऐसी कंपलेंट कहीं भी नहीं है। एक बात है कि जहां पर्वतीय क्षेत्र में जैसा एल०पी०पी०टी० हो या वी०एल०पी०टी० हो, वह काम करते हों, उनका जितने क्षेत्र में लाभ होना है वह कभी कभी नहीं होता क्योंकि पर्वत उसके बीच में आता है। इसलिए जितना एरिया वह कवर नहीं करते हैं उसके लिए दूसरा कोई ट्रांसमीटर लगाने की हमें जरूरत पड़ती है। कोई भी ऐसी जगह की शिकायत अगर माननीय सदस्य बताएंगे तो जरूर हम उसके बारे में सोचेंगे।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, यह मेरा सवाल सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। राजस्थान और गुजरात जो बोर्डर एरिया के स्टेट हैं, उसके बारे में सरकार ने पहले ही यह तय किया था कि पाकिस्तान की ओर से हमारे ऊपर सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है और इसलिए सरकार ने इन दोनों स्टेटों में टी०वी० स्टेशन डालने के लिए कहीं जगह भी ली, कुछ काम भी चल रहा है। यह सांस्कृतिक आक्रमण दिन-प्रति-दिन हमारी और बढ़ता जा रहा है। यह मामला इस सदन में बहुत बार उठ चुका है। तो सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इन दो स्टेट के बोर्डर एरिया पर कितने टी०वी० स्टेशन शुरू करने के काम शुरू किए हैं? कब किए हैं और वह कब पूरे होंगे?

श्री पी० एम० सईद: सभापति जी, यह एक दूसरा ही सवाल उठाया गया है। यह दो स्टेट में पाकिस्तान से हमारी कल्चरल हैरिटेज पर जो आक्रमण हो रहा है, इसके बारे में है।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: मंत्री जी, सुनिए। यह देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ टी०वी० स्टेशन का ही सवाल है। आपके पास सारी माहिती होनी ही चाहिए।

श्री पी० एम० सईद: मेरे पास तो है ही, मगर यह सवाल अलग सवाल है। ....**(व्यवधान)**....

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: तो दीजिए। इसमें कोई अलग नोटिस की जरूरत है ही नहीं।

SHRI P.M. SAYEED: Sir, I seek your protection. Sir, the question relates to the location of land identified for setting up a low power TV transmitter at Basot...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You have to put a separate question for that. (*Interruptions*)

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: यह डिफरेण्ट नहीं है, सर। ....**(व्यवधान)**.... देश की सुरक्षा का सवाल है, बिल्कुल देश की सुरक्षा का सवाल है। ....**(व्यवधान)**....

SHRI P.M. SAYEED: Even then I will be in a position to reply to his question. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, would you still like to say something?

SHRI P.M. SAYEED: Yes, Sir. Even though the question put by the hon. Member is not concerned with the main question, it is correct that our neighbouring countries, particularly Pakistan... (*Interruptions*)

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: मैंने पर्टिकुलरली बताया। ....**(व्यवधान)**....

SHRI P.M. SAYEED: Do you not want me to answer it? Please hear me. It is not arising out of this question but still I am trying to answer it. The cultural heritage of India is a model to the rest of the world. What we are doing is not for these two States alone but for the entire country. We are allocating large amounts of money which we collect from Doordarshan programmes. We have spent almost the entire money on building up our hardware, our machines and infrastructure so that we can prepare software for our cultural heritage and in a massive way, in an aggressive way, we will have to do that. That is the only answer to the broadcasting done by any of the neighbouring countries. There is nothing new in it. We are at it. We will go in a massive way.